



CSDS लोकनीतिसर्वेक्षण रिपोर्ट 2024

प्रलिस के लयः

[चुनाव आयोग](#), [लोकनीतिसर्वेक्षण रिपोर्ट 2024](#), [EVM](#), [सचचर आयोग रिपोर्ट](#), [CBI](#)

मेन्स के लयः

स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव कराना, चुनाव सुधार, स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव कराने के लयः समतयः की सफारः की सफारः

[स्रोतः द हदुः](#)

चरचा में क्यः?

हाल ही में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपग सोसाइटीज़ (CSDS) के लोकनीतिसर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा प्री-पोल स्टडी 2024 का आयोजन कयः, जसमें [EVM](#) तथा [भारत के चुनाव आयोग](#) पर वशवास एवं अन्य सामाजक-धार्मक मुद्दों जैसे वभिन्न मुद्दों पर जनता की राय सामने आई है।

लोकनीतिसर्वेक्षण के नषिकर्ष क्यः हैं?

- **संस्थाओं एवं प्रक्रयःओं में मतदाताओं का वशवासः**
 - भारतीय चुनाव आयोग पर जनता का वशवास कम हुआ है, यह वशवास वर्ष 2019 में 51% से गरकर वर्ष 2024 में केवल 28% तक सीमति रह गया है।
 - लगभग 17% उत्तरदाताओं का मानना है कः [सत्तारूढ दल](#), [इलेक्ट्रॉनक वोटग मशीनों \(EVM\)](#) में हेरफेर करने की अत्यधिक संभावना होती है।
 - उत्तरदाता कमोबेश उन लोगों में से थे जो महसूस करते थे कः [केंद्रीय जांच ब्यूरो \(Central Bureau of Investigation- CBI\)](#) तथा [प्रवरतन नदशलालय \(Enforcement Directorate- ED\)](#) जैसी एजेंसयः का प्रयोग राजनीतक प्रतशोध के लयः कयः जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कः एजेंसयः कानून के दायरे में रहकर काम कर रही हैं।
- **धार्मक बहुलवाद के लयः समर्थनः**
 - सर्वेक्षण में शामिल लगभग 79% लोगों का मानना है कः "भारत केवल हदुओं का नहीं, बल्कः समान रूप से सभी धर्मों का देश है", केवल 11% लोगों का मानना है कः "भारत केवल हदुओं का देश है"।
 - बहुलता में यह वशवास [शहरी कषेत्रों \(कस्बों में 85% और शहरों में 84%\)](#) में अधिक स्पष्ट था और बना स्कूली शकषा वाले लोगों (72%) की तुलना में [शकषति \(83%\)](#) में अधिक था।
- **अयोध्या में राम मंदरः का मुद्दाः**
 - केवल 22% सर्वेक्षणों में राम मंदरः के नरमाण को सरकार की 'सबसे उचतः काररवाई' बताया गया।
 - लगभग 24% लोगों का मानना है कः मंदरः मुद्दे से धार्मक वभाजन उत्पन्न होने की संभावना है।
- **अनुसूचतः जातः वरग में मुसलमःओं को आरकषणः**
 - लगभग 57% उत्तरदाताओं का मानना है कः हदुः और मुसलमः दलतः दोनों को नौकरयःओं में आरकषण प्रदान करने के लयः [अनुसूचतः जातः श्रेणी](#) का दायरा बढ़ाया जाना चाहयः।
 - 19% उत्तरदाताओं का मानना है कः अनुसूचतः जातः वरग में केवल हदुःओं को आरकषण दयः जाना चाहयः।
 - सामाजक न्याय की धर्मनरषेकष राजनीतः के लयः यह समर्थन [सचचर आयोग रिपोर्ट, 2006](#) और [रंगनाथ मशरः आयोग रिपोर्ट, 2007](#) द्वारा की गई सफारःओं की भी पुष्टः करता है, जो दृढता से दावा करता है कः [संवधान \(अनुसूचतः जातः\) आदेश, 1950](#) को स्थापतः संवैधानकः सधःधांतों के संबंध में फरः से पढ़ने की ज़रूरत है।

सर्वेक्षण के नषिकर्षों के नहतःार्थ क्यः हैं?

- EVM और चुनाव मशीनरी पर घटता वशवासः

- जनमत संग्रह सर्वेक्षण हाल के वर्षों में चुनाव मशीनरी पर घटते विश्वास पर लोगों की चिंता और बहस को सामने लाता है।
- यह चुनाव मशीनरी और EVM तथा VVPAT जैसे उपकरणों के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर को रोकने के लिये उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

■ असमति की राजनीति:

- सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में राजनीति में धर्म अभी भी एक प्रमुख कारक है।
- भारत में राजनीतिक दल अक्सर अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के लिये धार्मिक आधार पर मतदाताओं को लामबंद करते हैं, जिसे **असमति की राजनीति** के रूप में जाना जाता है।
- धर्म का राजनीतिकरण सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है: जैसे राजनीतिक बयानबाज़ी, **सांप्रदायिक एजेंडे के कारण धार्मिक हिसा**, भेदभाव और असहषिणता की घटना।

■ सार्वजनिक संस्थानों पर आरोप:

- CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में **राजनीतिक हस्तक्षेप** और इसे वपिक्षी दल के वरिद्ध एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने के कई आरोप लगे हैं।
- ऐसी धारणा है कि केंद्रीय एजेंसियाँ राजनीतिक संबद्धता या अन्य बाहरी वचारों के आधार पर **चुनदा व्यक्तियों** या संगठनों को नशाना बना सकती हैं।

■ रोज़गार, मुद्रास्फीति और अन्य मुद्दे:

- लोगों का मानना है कि हाल के दशकों में मजबूत आर्थिक विकास के बावजूद, बढ़ती श्रम शक्ति के साथ रोज़गार सृजन में तेज़ी नहीं आई है।
- हाल के वर्षों में बढ़ती खाद्य कीमतों ने देश की बड़ी आबादी और बेरोज़गारी के कारण भारत में मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

आगे की राह

- **चुनाव सुधार आयोग:** यह आयोग स्वतंत्र विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों और चुनाव अधिकारियों से बना हो सकता है।
 - चुनावी कानूनों, प्रक्रियाओं और संस्थानों में बदलावों की समीक्षा तथा सफ़ाई करने के काम के साथ।
- **केंद्रीय जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली:**
 - इन केंद्रीय निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति, स्थानांतरण और नषिकासन को वनियमिति करने के लिये सभी जाँच एजेंसियों को एक ही वैधानिक निकाय के तहत लाया जाए। हटाने के लिये राजनीतिक वदिवेष से परेति नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाँच के अधीन होनी चाहिये और कार्यकाल नषिचति होना चाहिये।
- **समावेशी नीतियाँ:** ऐसी नीतियाँ वकिसति तथा करियानवति करें जो हाशयि पर और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की ज़रूरतों एवं हतियों को प्राथमकितता दें।
 - इसमें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने और सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता को आगे बढ़ाने की पहल शामिल है।
- **मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी को लक्ष्य करना:** इसके लिये व्यापक आर्थिक नीतियों, संरचनात्मक सुधारों एवं लक्ष्यित हस्तक्षेपों के संयोजन की आवश्यकता होगी जैसे:
 - कुल मांग और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने के लिये **ब्याज दरों का समायोजन, कर नरिधारण और शासकीय व्यय** जैसे राजकोषीय नीति उपायों जैसे **मौद्रिक नीति उपकरणों** का उपयोग करना।
 - रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने और बेरोज़गारी कम करने के लिये **नरितर एवं समावेशी आर्थिक विकास** को बढ़ावा देना आवश्यक है।

दृष्टभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के इस्तेमाल को लेकर काफी वविवाद हुआ है। भारत में चुनावों की वशिवसनीयता सुनषिचति करने के लिये भारत नरिवाचन आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:(2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलय से संबंधति वविवाद नषिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3

(d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का वविचन कीजिये। (2022)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/csds-lokniti-survey-report-2024>

